International Journal of Business Economics and Management Research
Vol. 6, Issue 8, August 2015 Impact Factor: 4.963 ISSN: (2229-4848)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

भारतीय अर्थव्यवस्था पर घाटे के प्रबंधन के प्रभाव का एक अध्ययन

प्रा. वजय आनंदराव दरवडे
अर्थशास्त्र वभाग
शामरावबापू कापगते कला महा वद्यालय, साकोली
ता. साकोली जि. भंडारा - ४४१८०२

प्रस्तावना:

घाटे का प्रबंधन एक आधुनिक दिन का उपहार है। इ.स. **1929** से **1933** वैश्विक मंदी का दौर था। इस अव ध के दौरान व भन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई थीं। वैश्विक मंदी से पहले, एक धारणा थी क सरकारी बजट संतु लत होना चाहिए। अर्थशास्त्रियों की राय थी क अ धशेष सरकार का बजट कुछ समय के लए रहेगा ले कन यह घाटे में नहीं होना चाहिए। ले कन वैश्विक मंदी ने उस धारणा को बदल दिया है। मंदी का अनुमान अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के लए लगाया जाता था। प्रो कीन्स ने प्रभावी मांग को बढ़ावा देने के लए घाटे के बजट का समर्थन कया। सरकारी राजस्व में कमी ले कन उच्च व्यय को कम करने के लए घाटे के वत्तपोषण का उपयोग कया गया था। द् वतीय वश्व युद्ध के दौरान, युद्ध के लए भारी रकम की आवश्यकता थी। तब घाटे का वत्तपोषण व्यापक रूप से कया जाता था। आज की दुनिया में, अ वक सत देश अपने वकास के लए घाटे के वत्त का उपयोग कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की वक सत होती प्रकृति के कारण, जहाँ पछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के व भन्न क्षेत्रों से संसाधनों की निरंतर माँग रही है, इन क्षेत्रों से राजस्व प्राप्त करने की संभावना सी मत है।

पूरे देश के संतु लत वकास को सुनिश्चित करने के लए, सरकार ने व भन्न वकास योजनाएं शुरू कीं जिनमें संसाधनों की बड़ी हिस्सेदारी के बावजूद वकास अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा, जैसा क हमारा देश एक कल्याणकारी राष्ट्र है, सरकार समाज के सभी वर्गों के समान वकास के लए जिम्मेदार है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लए, सरकार को कई कल्याणकारी योजनाओं को दशकों तक भारी लागत पर लागू करना पड़ा है। सरकार के बजट में असंतुलन के पीछे यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है। कच्चे तेल के आयात में बढ़ोतरी और तेल की बढ़ती कीमतों ने भारत के आ थक संकट को बढ़ा दिया है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों के लए लगभग पूरी तरह से अपने आयात पर निर्भर है, इस प्रकार तेल आयात बिल पर भारी बोझ पड़ता है। इसके अलावा, भारत में चालू खाते के घाटे के व्यापक होने का एक और कारण यह है क देश की सोने की मांग आसमान छू रही है।

हाल के समय में, संरचनात्मक और सामरिक स्तरों पर देश के आ थक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, घाटे के प्रबंधन के कारण देश की वकास दर धीमी हो गई है। इस बढ़ते घाटे ने कई क्षेत्रों में बदलाव लाए हैं, ले कन इन परिवर्तनों ने न केवल हमारे देश की आ थक समस्याओं को हल कया

है, बल्कि उन्हें बढ़ाया है। वर्तमान शोध पत्र में, हम वर्तमान घाटे की वत्त व्यवस्था, मौजूदा वत्तीय समस्याओं और संभा वत समाधानों पर चर्चा करेंगे।

अनुसंधान निबंधों के लए प्रयुक्त अनुसंधान व धयाँ:

वर्तमान शोध प्रबंध के लए उपयोग की जाने वाली जानकारी और तथ्यों को वषय से संबं धत व भन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं, लेखों, समाचार पत्रों और वेब साइटों से संक लत कया गया है।

अनुसंधान के उद्देश्य:

प्रस्तुत शोध के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं।

1) देश में घाटे की वत्त की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।

2) मंदी के समय में यह पता लगाना क घाटे का प्रबंधन कैसे उपयोगी है।

3) पता करना क घाटे का प्रबंधन देश में कीमतों को कैसे प्रभा वत करता है।

4) आय और परिसंपत्तियों के वतरण पर घाटे के वत्त के प्रभाव का अध्ययन करना।

5) अनुसंधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर अर्थव्यवस्था की वकास प्र क्रया को बेहतर बनाने के लए सुझाव देना।

अनुसंधान की आवश्यकता और महत्व:

घाटे का प्रबंधन एक दोधारी तलवार है। इस लए, इसे बहुत सावधानी से उपयोग कया जाना है। इस संबंध में प्रो. केनेस कहते हैं की "कमी प्रबंधन को एक दवा के रूप में इस्तेमाल कया जाना चाहिए, न क एक दैनिक रोटी के रूप में," अन्यथा, उसे घाटे के प्रबंधन का खा मयाजा भुगतना पड़ेगा। इसका मतलब है क यदि सही तरीके से उपयोग कया जाए तो घाटे के प्रबंधन के कई लाभ हो सकते हैं। प्रो हैरिस ने यह स्पष्ट कर दिया है क नियोजन दुर्भाग्य का परिणाम है और घाटे का वत्तपोषण दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भू मका निभाता है। मतलब, घाटा वत्त वकास वत्त की एक शक्तिशाली तकनीक है और इसका अ वक सत देश की वत्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान है। मंदी के समय में घाटे का प्रबंधन कैसे उपयोगी है, देश की कीमतों पर इसका प्रभाव, आय और धन वतरण पर इसका प्रभाव, और घाटे के प्रबंधन के मामले में देश की वर्तमान स्थिति आदि जाणने हेतू प्रस्तुत शोध का वषय महत्वपूर्ण है

घाटे का प्रबंधन का मतलब है:

"जब सरकार का कुल व्यय सरकारी राजस्व से अ धक होता है, तो बजट घाटा दिखाया जाता है। इस घाटे को पूरा करने के लए जो व्यवस्था की जाती है उसे घाटे का वत्तपोषण कहा जाता है।

यह बजट घाटा आमतौर पर तीन तरीकों से भरा जाता है। यह इस तरह था- **1)** केंद्रीय खजाने से ऋण लेकर; **2)** लोगों से ऋण लेकर; **3)** नई मुद्राएँ बनाकर। फर सवाल यह है क इस बजट घाटे को कैसे और कस तरह से भरा जा सकता है। इसके लए दो दृष्टिकोण हैं।

1) पश्चिमी परिप्रेक्ष्य (अमेरिकी परिप्रेक्ष्य): अ धकांश पश्चिमी देशों में, वशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में घाटे के वत्तपोषण पर एक वशेष दृष्टिकोण है। अमेरिकी दृष्टिकोण से, जब सरकारी व्यय सरकारी राजस्व से अ धक होता है और घाटे को जनता से उधार लेकर कवर कया जाता है, तो इसे घाटे का प्रबंधन माना जाता है।

2) भारतीय परिप्रेक्ष्य: भारतीय परिप्रेक्ष्य अमेरिकी दृष्टिकोण से अलग है। भारतीय दृष्टिकोण से, जब सरकार का कुल राजस्व (राजस्व + पूंजी) सरकार के कुल खर्च से कम होता है, तो बजट घाटा दिखाया जाता है। घाटे का प्रबंधन तब होता है जब सरकार रिजर्व बैंक में अपने खजाने से पैसा निकालती है या रिजर्व बैंक और चैंबर ऑफ कॉमर्स से उधार लेती है या कमी को पूरा करने के लए नए नोट जारी करती है। बजट घाटे को बंद करने का यह उपाय मुद्रा पर मुद्रा के प्रभाव को बढ़ाता है। कुल घाटे का यह वचार मूलतः दो चीजों पर आधारित है।

1) बजट घाटे का आकलन करते समय, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के राजस्व और पूंजी दोनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

2) दूसरे, घाटे के प्रबंधन के परिणामस्वरूप धन की आपूर्ति बढ़ाई जानी चाहिए।

इस कारण से, इस प्रकार के वत्त को घाटे की धन आपूर्ति भी कहा जाता है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार, यदि घाटे का प्रबंधन कया जाता है, तो मुद्रा का प्रसार होना स्वाभा वक है। इतना ही नहीं, ले कन इस धन प्रबंधन से धन की आपूर्ति बढ़ जाती है और परिणामस्वरूप कमो डटी की कीमतें बढ़ने की संभावना है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर घाटे के प्रबंधन का प्रभाव:

घाटे के वत्तपोषण का देश की अर्थव्यवस्था पर व भन्न प्रभाव पड़ता है। घाटे के वत्तपोषण के परिणामों पर चर्चा करते समय दो मुख्य वचार हैं।

1) कीमतों पर प्रभाव: सरकार का कुल राजस्व कम होने और व्यय अ धक होने पर घाटा प्रबंधन कया जाता है। उच्च सरकारी खर्च से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। नतीजतन, माल की उनकी मांग बढ़ जाती है, ले कन माल की आपूर्ति मांग के रूप में नहीं बढ़ सकती है। परिणामस्वरूप, वस्तुओं की आपूर्ति और मांग में असंतुलन होता है और कीमतें बढ़ने लगती हैं। ऐसे मामलों में, लोग वा णज्यिक बैंकों से ऋण लेते हैं और इसका उपयोग क्रेडें शयल बनाने के लए कया जाता है। प्रत्ययों के गठन के कारण, मूल्य स्तर अ धक से अ धक बढ़ जाता है। इससे फूला हुआ राज्य होने की संभावना है। इस लए, घाटे के प्रबंधन और वा णज्य मंडलों के गठन पर उ चत नियंत्रण होना आवश्यक है। भारत में यही स्थिति है।

2) वतरण पर प्रभाव: कमी प्रबंधन एक वस्तु के मूल्य स्तर को बढ़ाता है। यह उत्पादकों को अ धक उत्पादन करने के लए प्रोत्साहित करता है। मूल्य वृ द्ध से उनके लाभ मार्जिन में वृ द्ध हुई है। लाभ मार्जिन बढ़ने से निवेश की मात्रा बढ़ जाती है। बढ़ती कीमतों से श्र मकों की खपत और निश्चित मजदूरी अर्जक भी कम हो जाते हैं। उनकी वास्त वक आय कम हो जाती है, ले कन उत्पादकों, व्यापारियों और व्यापारी वर्ग की वास्त वक आय बढ़ने लगती है। संक्षेप में, घाटे के प्रबंधन से आय और धन के वतरण में असमानता पैदा होती है। बढ़ती कीमतों से फ़ायदेमंद वर्ग की आय में वृ द्ध होती है। ले कन श्र मकों की आय और निश्चित मजदूरी कमाने वालों की संख्या में अ धक वृ द्ध

नहीं होती है। सरकार का उद्देश्य वास्त वक आय और धन का समान वतरण सुनिश्चित करना है। ले कन घाटे का वत्त सर्फ ऐसा करने का प्रबंधन करता है। बेशक, उत्पादकों, व्यापारियों और व्यापारियों की आय में पर्याप्त वृ द्ध हुई है। यह उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाता है। ले कन कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर आय धारकों पर पड़ता है और उनके जीवन स्तर में गरावट आती है। यह अ धकतम सामाजिक कल्याण के सद्धांत में बाधा डालता है। यह भारत की वर्तमान स्थिति है।

भारत में, सरकार पंचवर्षीय योजना के लए धन जुटाने के मामले में तटीय वत्त को बहुत महत्व देती है। पहली पंचवर्षीय योजना में कुल खर्च का **17%** की कमी का प्रबंधन कया गया था। जो **333** करोड़ रुपये था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के लए घाटा **954** करोड़ रुपये, तीसरी पंचवर्षीय योजना के लए **1133** करोड़ रुपये, चौथी पंचवर्षीय योजना के लए **2060** करोड़ रुपये, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के लए **3560** करोड़ रुपये, छठी पंचवर्षीय योजना के लए **15684** करोड़ रुपये और सातवीं पंचवर्षीय योजना के लए **34669** करोड़ रुपये की लागत थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में **4.6%** की कमी के साथ तैयार कया गया था। इससे महंगाई बढ़ी और महंगाई बढ़ी।

भारत **2008** में तीन अभूतपूर्व संकटों से पी ड़त वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ, राजकोषीय समेकन और उच्च जीडीपी वकास की राह पर था। पहला है पेट्रो लयम की कीमतों में बढ़ोतरी, दूसरा है जिंस की कीमतों में बढ़ोतरी और तीसरा है वक सत अर्थव्यवस्थाओं की वत्तीय प्रणाली की वफलता। जब क उभरती बाजार अर्थव्यवस्था ने संकट का कारण नहीं बनाया, संकट का संयुक्त प्रभाव भारत सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लए एक गंभीर चुनौती थी। तदनुसार, राजकोषीय नीति में वकास प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित कया जाना था। परिणामस्वरूप, वत्तीय समेकन को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया और वत्तीय वर्ष **2007-08** के लए संग्रह को FRBM अ धनियम के तहत रोक दिया गया। अगस्त **2012** में, भारत सरकार ने वत्तीय जीत का खाका सुझाने के लए डॉ. वजय केलकर की अध्यक्षता में एक स मति का गठन कया। सरकार ने आ र्थक एकीकरण पर केलकर स मति की कई सफारिशों पर सहमति व्यक्त की और राजस्व व्यय में अंतर को कम करने के उद्देश्य से उन्हें लागू करने के लए कई कदम उठाए। भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे पर मध्याव ध खर्च के बयान की शुरुआत की। जिसके तहत प्राथ मकता प्राप्त योजनाओं और अन्य योजनाओं के लए संसाधनों को आवंटित करने के लए नई पहल करने के उद्देश्य से लागत साधकों के लए तीन साल चलाए गए थे जिन्होंने अपने उपयोग की अव ध पूरी कर ली है। सरकार ने कमी को दूर करने के लए केंद्रीय अनुदान पर खर्च को सी मत करने की भी मांग की।

वत्तीय वर्ष **2012-13** में आ र्थक वकास का पहला और दूसरा भाग दो भागों में वभाजित कया गया था। **2012-13** की पहली छमाही को कुछ वत्तीय त्रुटियों द्वारा चह्नित कया गया था। हालां क, वत्तीय स्थिरीकरण उपायों में साल के मध्य में सुधार हुआ, ले कन **2012-13** की दूसरी छमाही में महत्वपूर्ण वत्तीय सुधार कए गए। वर्ष के उत्तरार्ध में राजकोषीय सुधारों के कारण, सकल राजकोषीय घाटा (GFD) **2011-12** में **5.7** प्रतिशत से बढ़कर **2012-13** में सकल घरेलू उत्पाद का **4.9** प्रतिशत रहा। इस प्र क्रया में मुख्य रूप से करों और गैर-कर

राजस्व में कमी के कारण लागत को कम करके जीएफडी को नियंत्रण में रखा गया था। **2013-14** में जीडीपी के **46** प्रतिशत तक पहुंचने के लए सकल राजकोषीय घाटे में नियोजित कमी को कम करने के लए वनिवेश, दूरसंचार और सब्सिडी पर व्यय की उम्मीद थी। हालां क, राजस्व-आधारित वत्तीय समेकन की सफलता निवेश जलवायु और वकास की बहाली पर निर्भर करती है। जहां तक खर्च का सवाल है, **2013-14** में पूंजी और योजना व्यय में तेजी से वृ द्ध के लए बजट में प्रावधान कया गया है। **2012-13** में, पूंजीगत व्यय का पुनर्पूंजीकरण **34.1** प्रतिशत (संशो धत अनुमान) से बढ़ा। **2013-14** में, पूंजीगत व्यय में जीएफडी अनुपात **39.39** प्रतिशत था। यद्य प योजना की रूपरेखा **2013-14** में अ धक रखी गई थी, ले कन योजना के पहले दो वर्षों (यानी, **2012-13** और **2013-14**) में बारहवीं पंचवर्षीय योजना की पूरी अव ध के लए केंद्रीय योजना के लए बजटीय समर्थन दिया गया था। यह अनुमानित कुल बजट समर्थन का **24.4** प्रतिशत था।

अनियोजित व्यय की सकारात्मक वशेषताओं में से एक यह है क **2013-14** में जीडीपी के **2%** तक सब्सिडी को सी मत करने की परिकल्पना की गई थी। सरकार ने उम्मीद की थी क डीजल की कीमतों के एक चरणबद्ध वनियमन से ईंधन सब्सिडी को नियंत्रित करने में मदद मलेगी, ले कन वनिमय दरों में बढ़ोतरी से **2013-14** में ईंधन और उर्वरक सब्सिडी पर दबाव बढ़ गया। तेल कंपनियों की कम वसूली और क्षेत्र में प्रच लत प्रशासनिक मूल्य प्रणाली के अवशेषों और वनिमय दर के अवमूल्यन के कारण कीमतों में देर से रिकवरी तेजी से बढ़ी और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृ द्ध हुई। **2013-14** में खाद्य सब्सिडी पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अ धनियम का प्रभाव प्रबंधनीय था, ले कन अगले कुछ वर्षों में वत्तीय दबाव बढ़ गया। मुख्य चंता यह थी क खाद्य सुरक्षा अ धनियम के अ धनियमन के साथ, **2013-14** में बजटीय खाद्य सब्सिडी को नियंत्रित करना मुश्किल होगा, और यह कया। इस प्रकार घाटे के वत्तपोषण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है।

निष्कर्ष:

अध्ययन में पाया गया क आ र्थक वकास की प्र क्रया में, देश की कमो डटी राष्ट्रीय आय लंबे समय तक बढ़ती रहती है। अ वक सत या अल्प वक सत देशों में आ र्थक वकास के लए योजना को अपनाया जाता है। नियोजन कार्य के लए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। यह प्रावधान घाटे के वत्तपोषण के माध्यम से कया जाता है; संक्षेप में, घाटे का प्रबंधन करके आ र्थक वकास प्राप्त कया जा सकता है। ऐसे में कमो डटी का प्राइस लेवल बढ़ने की संभावना है। ले कन ध्यान रखा जाना चाहिए क यह प्रति वर्ष **2-3%** से अ धक न हो। संक्षेप में, यदि घाटे के प्रबंधन का सावधानीपूर्वक और कुशलता से उपयोग कया जाए तो आ र्थक वकास हो सकता है।

सुझाव:

1) यदि घाटे के प्रबंधन का उपयोग उत्पादकता वृ द्ध के साथ-साथ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की ओर कया जाता है, तो इसके अनुकूल परिणाम होंगे। साथ ही, यदि रोजगार सृजन पर वशेष जोर दिया जाता है, तो बेरोजगारों

को रोजगार मलेगा और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। परिणामस्वरूप, उनकी खपत में वृद्ध होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। सरकार को इस दिशा में प्रयास करने चाहिए।

2) केवल घाटे के प्रबंधन के कारण अधकतम सामाजिक कल्याण की गारंटी देना संभव नहीं है, इस लए एक अन्य वैकल्पिक मार्ग पर भी वचार कया जाना चाहिए।

3) वत्तीय उद्देश्यों को पूरा करने के लए, कर, व्यय, ऋण और नवेश नीतियों को घाटे के प्रबंधन के अनुरूप तैयार कया जाना चाहिए।

4) कसी भी राजकोषीय वत्त का मूल्यांकन उसके आधार पर कया जाना है। कमी प्रबंधन को उत्पादक कार्यों में उचत और कुशलता से उपयोग कया जाना चाहिए। इससे अनुकूल परिणाम मल सकते हैं। ले कन अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल न कया जाए तो इसके गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं।

5) डे फ सट मैनेजमेंट का इस्तेमाल दवा के रूप में कया जाना चाहिए, दैनिक रोटी की तरह नहीं।

ग्रंथ सूची:

1) भारतीय अर्थव्यवस्था , रुद्रदत्त एवं के. पी. एम. सुंदरम, एस. चाँद एंड कंपनी, नई दिल्ली (हिन्दी)
2) भारतीय अर्थव्यवस्था , डॉ. घाटणे व वावरे, निराली प्रकाशन, पुणे, जुलै- 2010
3) स्पर्धा परीक्षा अर्थशास्त्र -2, आ र्थक व सामाजिक वकास, डॉ. करण जी. देसले, दीपस्तंभ प्रकाशन, जळगाव, दूसरी आवृती, ऑगस्ट 2012.(मराठी)
4) सूचना बुलेटिन, लोकसभा स चवालय शोध एवं सूचना प्रभाग, जुलाई 2014
5) The Indian Economy - Sanjiv Verma, Unique Publication, Jan 2013.
6) Economic survey of India - 2011-12, 2013-2014
7) Indian Economy - Misra & Puri, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2010.
8) Indian Economy - Ramesh Sing, MeGraw Hill Education, June 2012

समाचार पत्र: नवभारत, लोकमत, टाइम्स ऑफ इं डया

वेबसाइट:

- https://www.rbi.org.in/hindi/
- https://www.rbi.org.in/hindi1/Upload/Publications/PDFs/0SFINH300311_F.pdf